Salient Features of Ninth Plan

1835. DR. ALLADI P. RAJKUMAR:
SHRI K.M. SAIFULLAH:
DR. Y. LAKSHMI PRASAD:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the draft Ninth Plan has been finalised;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) if not, the reasons for delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) Yes, Sir.

(b) The Ninth Five Year Plan (1997-2002) is based on the priorities envisaged in the Approach Paper to Ninth Plan and also the special emphasis on areas including the Special Action Plan (SAPs). The focus of SAPS are on (a) doubling of food production in 10 years; (b) expansion and improvement of social infrastructure; (c) expansion and improvement of physical infrastructure and financial services; (d) unveiling a National Water Policy and (e) making India a global Information Technology power.

The Ninth Five Year Plan envisages an average growth rate of 6.5 per cent per annum in Gross Domestic Product (GDP). An average growth rate of around 7 per cent needs to be realised in the remaining three years to achieve the average GDP target growth rate of 6.5 per cent during the Ninth Plan period. The Ninth Plan envisages a total Public Sector Outlay of Rs. 859, 200 crores which includes a Gross Budgetary Support of Rs. 374,000 crores.

(c) Does not arise.

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार

1836. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों का वर्ष-वार प्रतिशत क्या है और गरीबी रेखा की सीमाएं क्या हैं;

(ख) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के उत्थान के लिए समय-समय पर आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या इन योजनाओं से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए; और

(घ) यदि हां, इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक उपाए किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) योजना आयोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा करवाये गये पंचवार्षिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से लगाता है। पिछला ऐसा सर्वेक्षण 1993-94 में करवाया गया था। इसलिये पिछले पांच वर्षों से गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रतिशत के अनुमान उपलब्ध नहीं है। 50 वें दौर के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित, 1993-94 के लिये उपलब्ध, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के नवीनतम अनुमानों के अनुसार 1993-94 में 35.97 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही थी। यद्यपि गरीबी के प्रभाव क्षेत्र का मापन व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का एक मोटा-अनुमान, औसत परिवार आकार के जरिए लगा पाना संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के परिवारों का आकार 5.458 तथा शहरी क्षेत्रों में 5.386 मानते हुये, जैसा कि एनएसएस के 1993-94 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से विदित हुआ था, व्यक्तियों का उपर्युक्त प्रतिशत परिवारों के 31.5 प्रतिशत के सदृश है। वर्ष 1993-94 एवं 1996-97 के लिये राज्यवार गरीबी की रेखाए क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दी गयी हैं। **(नीचे देखिए)**